चार लाख रोजगार देने के लक्ष्य पर नजर

जनसंख्या नियोजन ● एमएसएमई सेक्टर में नौकरियों की सबसे अधिक संभावनाएं

जागरण संवाददाता ● लखनऊ : एक फरवरी को केंद्रीय बजट आ रहा है। बजट के पिटारे में क्या होगा, यह तो खुलने पर ही पता चलेगा, लेकिन उद्यमियों को उम्मीद है कि यदि सरकार ने एमएसएमई सेक्टर पर दरियादिली दिखाई तो नौकरियों और रोजगार की अपार संभावनाएं पैदा होंगी। फिलहाल जो स्थिति है उसके आधार पर वित्तीय वर्ष के अंत तक चार लाख नौकरियों का लक्ष्य है जिसे पूरा करने का दावा किया जा रहा है।

लखनऊ कभी बाबुओं और अफसरों का शहर कहा जाता था, लेकिन पिछले साल फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में दो लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों से अब आर्थिकी बदल रही है। निवेश प्रस्तावों से करीब चालीस हजार करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास हो चुका है, जिनसे लाखों नौकरियों और रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। उद्यमियों का कहना है कि सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए बजट में विशेष पैकेज प्रदान करे तो रोजगार के इन आंकड़ों में बेहिसाब बढ़ोतरी हो सकती है।

50 हजार से ज्यादा महिलाएं रोजगार से जुड़ीं : उद्योग विभाग के आंकड़ों में पिछले एक साल में छोटी बड़ी पचास हजार नई एमएसएमई की स्थापना हुई और साढ़े तीन लाख युवाओं को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर मिले हैं। मौजूदा समय में करीब पौने दो लाख एमएमएमई इकाइयां पंजीकृत हैं। विभागीय योजनाओं के माध्यम से 50 हजार से अधिक महिलाएं रोजगार से जुड़कर आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं।

जीएसटी का सरलीकरण होना जरूरी : सरकार को इस बार बजट में एमएसएमई सेक्टर को प्राथमिकता में रखना चाहिए। एमएसएमई सेक्टर ही देश की आर्थिकी विकास की मुख्य धुरी है। सभी बजट की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं। एमएसएमई के लिए। जीएसटी का सरलीकरण होना बहुत जरूरी है। एमएसएमई में अपेक्स एंड माइक्रो इंडस्ट्री में लेबर के लिए सेस प्रकरण होना चाहिए, जिससे सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाए।

चिकन के कपड़े दिखाती महिला ● जागरण आर्काइव

बढ़ रहे रोजगार के अवसर

प्रमुख निवेश के प्रस्ताव

सेक्टर	प्रस्ताव	निवेश
एमएसएमई	201	4557.95
एनर्जी	15	63060
तकनीकी शिक्षा	21	1625.49
हाउसिंग	167	39269.9
पशुपालन	35	328.74
शहरी विकास	27	17502.6
यूपीसीडा	35	13999.9
आइटी, इलेक्ट्रानिक्स	25	4417.5
मेडिकल हेल्थ	22	6440.37

(सभी करोड़ में)

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद से कई योजनाएं धरातल पर हैं। प्रत्येक सेक्टर में निवेशकों के अनुकूल माहौल तैयार है। इससे रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। लघु उद्योगों के साथ ही एक जिला एक उत्पाद के तहत कामगार जोड़े गए हैं। सेवा के क्षेत्र में भी विकास हो रहा है। अब तक 1.70 लाख एमएसएमई इकाइयां पोर्टल पर पंजीकृत हो चुकी हैं।

-मनोज चौरसिया, उपायुक्त उद्योग

एमएसएमई के तहत पंजीकृत कराने की नियमावली सरल होनी चाहिए। जैसे ब्लाक स्तर हम महिलाओं से काम कराते हैं, लेकिन उनका पंजीयन और विवरण मांगा जाता है, जबकि कंपनी तो पंजीकृत है। इस पर उन्हें पंजीकृत मान लिया जाए। इसके अलावा जिले स्तर पर काम करने वाली इकाइयों को लोन के बजाय ग्रांट दी जाए, जिससे कारोबार को आगे बढ़ाने में मदद हो सके।

-ऋचा सक्सेना, उद्यमी

सरकार को बजट में एमएसएमई सेक्टर को प्राथमिकता देनी चाहिए। एमएसएमई सेक्टर ही देश की आर्थिकी विकास की धुरी है। सभी लोग बजट की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं। एमएसएमई के लिए। जीएसटी का सरलीकरण होना अति आवश्यक है। एमएसएमई में अपेक्स एंड माइक्रो इंडस्ट्री में लेबर के लिए भी सेस प्रकरण होना चाहिए, जिससे सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े।

-विकास खन्ना, अध्यक्ष इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन लखनऊ

चिकन हैंडीक्राफ्ट की उपयोगिता मनरेगा जैसी है, जहां कारीगर को घर बैठे काम मिलता है। चिकन इंडस्ट्री में रोजगार सृजन की अपार क्षमता है। चिकन का एक सेट बनाने में सात से दस लोगों को रोजगार मिलता है। यदि बजट में इसको स्पेशल पैकेज दिया जाए तो लाखों और लोगों को रोजगार मिल सकता है। विशेष पैकेज के साथ ही इसे विदेश-देश में प्रोत्साहित किया जाए। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में काम करने वाले कारीगरों को कुछ इंसेंटिव भी मिलना चाहिए।

-राजीव महेंद्रू, उपाध्यक्ष, लखनऊ चिकनकारी हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन